दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार, 20 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 201

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा से 10 पिस्तौल बरामद

श्रीनगर (आरएनएस)। सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान 10 पिस्तौल सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किए। पुलिस ने कहा कि एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सेना और पुलिस ने करनाह तहसील के हाजिन मोहल्ले में भारी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए। पुलिस ने बताया कि बरामद हथियार और गोला-बारूद में 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड और 5 ग्रेनेड शामिल हैं।

सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ जवान का हुआ निधन, 12 घायल

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में आज एक सडक़ दुर्घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान का निधन हो गया, जबकि अन्य 12 घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हैदरपोरा बाईपास क्षेत्र में एक ट्रक ने सीआरपीएफ के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे सीआरपीएफ के 13 जवान घायल हो गए। सभी घायल सीआरपीएफ जवानों को हमहामा के बीएसएफ अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान कांस्टेबल एमएन मणि ने दम तोड़ दिया। सीआरपीएफ के एएसआई जसराज और कांस्टेबल सुशांत विश्वास को सेना के 92 बेस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

काबुल में स्कूल के पास हुआ जबरदस्त धमाका, 25 बच्चों की मौत

काबूल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर धमाकों से दहल उठी है। राजधानी काबुल में एक स्कूल के पास दो धमाके हुए हैं। इस हमले में 25 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि राजधानी काबुल के पश्चिमी हिस्से में एक स्कूल के पास दो जबरदस्त धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 25 बच्चों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुई हैं। ये धमाका राजधानी के दस्त-बार्ची इलाके में हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि दूसरा धमाका अब्दुरहीम शाहिद हाई स्कूल के पास हुआ है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है। आमतौर पर अफगानिस्तान में होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट लेता आया है।

चीन के शंघाई में कोविड से बुरा हाल, 7 लोगों की मौत , 21 की हालत गंभीर

शंघाई। चीन का कोरोना वायरस से बुरा हाल है। चीन के शंघाई शहर में कोविड से और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड की इस नई लहर में शंघाई में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 लोगों की हालात गंभीर है। शंघाई में पिछले सप्ताह की तुलना में कोरोना के केसों में गिरावट के बावजूद शहर में कुल ताजा मामलों की संख्या अधिक बनी हुई है। शंघाई स्वास्थ्य प्राधिकरण के एक अधिकारी वू कियान्यु ने बताया है कि 3,084 स्थानीय मामले और 17,332 स्थानीय एसिम्प्टोमैटिक संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं। अधिकारी ने बताया है कि 26 फरवरी से 18 अप्रैल तक शहर में 27,613 स्थानीय पुष्ट मामले सामने आए हैं और 21,717 अस्पताल में भर्ती मरीज में हैं, जिसमें से 21 लोगों की हालात गंभीर है। चीन के स्वास्थ्य मंत्री मा शियाओवेई ने कहा है कि देश कोविड 19 को लेकर अपने जीरो-टोलरेंस के दृष्टिकोण को जारी रखेगा। यदि चीन ने नियंत्रण को ढीला कर दिया तो बड़ी संख्या में बुजुर्गों और बच्चों को खतरा होगा, जो अर्थव्यवस्था और समाज के स्थिर विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि आवश्यकताओं में किसी भी तरह की छूट या कमी, सुई के आकार की कोई भी खामी महामारी को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। चीन के फाइनेंशियल हब शंघाई में कोविड के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने बेहद सख्त लॉकडाउन लगा दिया है जिससे आपूर्ति की समस्यायों के साथ ही व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने कोविड से संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन में डाल दिया है और न्यूक्लिक एसिड के जरिए टेस्टिंग कर रही है।

जनजातियों की भाषा, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत - मुख्यमंत्री

❐ **राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदिवासी समाज को अन्य समाज से जोड़ने के लिए सेतु का कार्य करेगा : मुख्यमंत्री**

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उन्हें हमें बचाना है। इसके लिए जनजातीय भाषा, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का पहली बार आयोजन हो रहा है। यह आयोजन सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य समाजों और जनजातीय समाज के बीच निश्चित रूप से सेतु का काम करेगा। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुजूर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सरजियस मिंज, सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति डी.डी. सिंह भी मंचस्थ थे।

तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव- राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बड्डघेल ने पद्म लोकनायक हलधर नाग, साकीनेती रामचंद्रया और अर्जुन सिंह धुर्वे को शॉल और नारियल भेंटकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने प्रख्यात कवि पद्म हलधर नाग को सम्मानित करते हुए आत्मीयता से गले लगाया। उन्होंने समारोह में देशभर से पहुंचे विख्यात साहित्यकारों, रचनाकारों, विश्वविद्यालयों के अध्येताओं, शोधर्थियों, विषय-विशेषज्ञों, नृतक दलों, चित्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा से बस्तर तक अनेक जनजातियां निवास करती हैं और उनकी भाषा-शैली भी अलग-अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों में नक्सली समस्या कम हुई है। अब छत्तीसगढ़ की चर्चा देश-दुनिया में यहां की समृद्ध संस्कृति के लिए हो रही है। हमारी सरकार ने जनजातियों की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कराया, जिसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इससे देश-दुनिया के लोगों को छत्तीसगढ़ को जानने और समझने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि विश्व में बहुत सी जनजातियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, जिससे उनकी संस्कृति विलुप्त हो रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूली स्तर भी पहल की है। इसके लिए प्रदेश में 16 प्रकार की बोली में पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है। अब प्रदेश में कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं। जनजातीय भाषाओं, बोलियों, कला-परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए बस्तर में बादल अकादमी की स्थापना की गई है। इसी तरह की अकादमी अन्य जनजातीय बहुलता वाले जिलों में भी स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य, नृत्य, चित्रकारी का प्रदर्शन निश्चित रूप से सभी समाज को जोडऩे में सेतु का कार्य करता है।

छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी हितों के संरक्षण- मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी हितों के संरक्षण के प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार में आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वन अधिकार पत्र प्रदान सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके रोजगार के लिए वन क्षेत्रों में फलदार वृक्ष लगाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, इससे वनों में वृक्षों के संरक्षण के साथ ही वनवासियों को उनकी जरूरत की चीज उपलब्ध होगी। इसी प्रकार प्रदेश में पहले 7 लघु वनोपजों की खरीदी की जाती थी, अब 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही इन लघु वनोपजों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कार्य कर रही है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की। उन्होंने कहा कि जंगल का संरक्षण आदिवासी करते हैं। देश में 80 प्रतिशत वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य से होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए हैं। जिसका लाभ जनजातीय समाज के बच्चों को भी मिल रहा है। प्रदेश में प्रयास विद्यालय के माध्यम से जनजातीय समाज के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय परंपरा और साहित्य को लिपिबद्ध किया जाना जरूरी है। अब आदिवासी समाज में इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के साथ ही तीन दिन तक यहां राज्य स्तरीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता एवं नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनजातीय साहित्य प्रचार-प्रसार और विकास के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। जिसमें विशेष रूप से जनजातीय विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों को प्रदर्शन सहविक्रय की व्यवस्था स्टॉल के माध्यम से की गई है। साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों जैसे हस्तशिल्प विकास बोर्ड, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, औषधि पादप बोर्ड, जनसम्पर्क विभाग, माटी कला बोर्ड, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के स्टॉल भी लगाए गए हैं। स्टॉल में गढक़लेवा तथा बस्तरिहा व्यंजन का स्वाद भी जनसमूह ले सकेंगे।

कोविड-19 से लडऩे वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 180 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी), कोविड-19 से लडऩे वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल, 2022 से 180 दिन और बढ़ा दी गई है। इस बीमा पॉलिसी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना जारी रखा जा सके जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त हैं। इस आशय का एक पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2022 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों (स्वास्थ्य)/प्रधान सचिवों (स्वास्थ्य)/सचिवों (स्वास्थ्य) को उनके संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य कर्मियों के बीच व्यापक प्रचार करने के लिए जारी किया गया है। पीएमजीकेपी को 30 मार्च, 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं और सीधे संपर्क में रहे हैं तथा जिन्हें कोविड-19 से प्रभावित होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अप्रत्याशित स्थिति के कारण राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/अस्पतालों कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा विशेष रूप से तैयार अस्पतालों द्वारा अधिग्रहण किए गए निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/एडोक/आउटसोर्स स्टाफ भी पीएमजीकेपी के अंतर्गत आते हैं। योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक उन 1905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटारा किया जा चुका है, जिनकी कोविड संबंधित कार्यों के लिए तैनात किए जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी।

यूपी में मंदिरों, धार्मिक स्थलों की बढ़ाई जा रही सुरक्षा

लखनऊ (आरएनएस)। इस महीने की शुरूआत में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी एजेंसियां राज्य के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा रही है। पुलिस, स्थानीय अधिकारियों के साथ, बलरामपुर में तुलसीराम शक्तिपीठ, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, देवीपाटन, अयोध्या, मिजार्पुर, मथुरा और वाराणसी के मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है।

इन सभी मंदिरों में रेड, येलो और ग्रीन जोन को मिलाकर सुरक्षा के तीन स्तर बनाए जाएंगे।

रेड जोन को सिक्योर जोन के रूप में भी जाना जाता है जहां हाई-एंड सर्विलांस और सिक्योरिटी लगाई जाएगी, इसके बाद येलो जोन को सेमी-सिक्योर जोन और ग्रीन जोन को पब्लिक जोन के रूप में जाना जाता है।

पुलिस ने कहा कि ऐसी व्यवस्था श्री कृष्ण जन्मभूमि और आगरा में शाही ईदगाह में भी की गई है।

महत्वपूर्ण मंदिरों और तीर्थों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ द्वारा मथुरा और अयोध्या के मंदिरों की सुरक्षा में भी सहयोग किया जा रहा है, जबकि वाराणसी मंदिर के लिए गुजरात में अक्षरधाम मंदिर जैसी सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि खतरे की आशंका और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का ऑडिट किया जा रहा है और इसे स्थापित किया जाएगा।

ज्ञात हो कि 3 अप्रैल को आईआईटी बॉम्बे के स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पीएसी के दो जवानों पर हंसिया से हमला किया और धार्मिक नारे लगाते हुए सुना गया।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बीपीओ सेंटर का निरीक्षण

❐ **प्रशिक्षणार्थियों से बात कर प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों से हुए रूबरू**

❐ **कलेक्टर ने बीपीओ सेंटर में संचालित गतिविधियों की दी जानकारी**

❐ **बीपीओ सेंटर में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर सुलभ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का किया गया बेहतरीन प्रयास**

राजनांदगांव (आरएनएस)। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत टेड़ेसरा में संचालित आरोहण बीपीओ सेंटर का निरीक्षण किया। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए राजनांदगांव जिले के प्रवास पर थे। यहां उन्होंने पहुंचकर बीपीओ सेंटर में संचालित गतिविधियों से रूबरू हुए। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने सेंटर में संचालित गतिविधियों से मंत्री सिंधिया को रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि बीपीओ सेंटर में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर सुलभ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। यहां जिले के साथ-साथ आसपास के अन्य जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर एवं कौशल में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भविष्य में आदिवासी आबादी को भी रोजगार के अवसर मिले इस उद्देश्य से मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बिरेझर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को 1000 नौकरी की पेशकश की गई है। उन्होंने बताया कि आरोहण बीपीओ के तहत वर्ष 2022-23 में कार्यरत सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुए लगभग 2000 सीटों में कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु भविष्य की कार्य योजना निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आगामी समय में इसका संचालन 24 घंटे सातों दिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक आरोहण बीपीओ सेंटर पूर्णत: बंद रहा। इसके बाद 1 सितम्बर 2020 से जिला प्रशासन द्वारा इसे पुन: प्रारंभ किया गया। पहले 350 सीट थी जिसे जिला प्रशासन द्वारा बढ़ाकर 1 हजार किया गया। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बीपीओ सेंटर की संचालन व्यवस्था और कार्यक्रम को देखकर प्रसन्नता व्यक्त किये।

उल्लेखनीय है कि बीपीओ के माध्यम से देश की ख्याति प्राप्त मार्केटिंग कार्पोरेट कंपनियों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। बीपीओ सेंटर का संचालन ट्रिपल पी मॉडल के तहत जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा टेक्नो बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध स्थापित करते हुए संचालन किया जा रहा है। बीपीओ संचालन से जिले तथा आसपास के अन्य जिले के लगभग 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में कार्यरत कंपनियों के अतिरिक्त अन्य ख्याति प्राप्त कार्पोरेट संस्थाओं से समन्वय कर इनका कार्य संपादन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

तेलंगाना ने स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना सरकार ने अपना स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

यह देखते हुए कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राज्य का अगला फोकस क्षेत्र है, तेलंगाना के आईटी, उद्योग और एमएयूडी मंत्री के.टी. रामा राव ने कहा कि स्पेसटेक उद्योग में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी का समर्थन करने वाले राष्ट्रीय सुधारों के साथ, तेलंगाना उस नवाचार का समर्थन करेगा जो होने वाला है।

मंत्री ने कहा कि अतीत में, हमने कई विदेशी निजी कंपनियों को तकनीकी प्रगति के साथ दुनिया को अचरज में डालते देखा है, लेकिन उनमें से अधिकांश को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बनाया है। लेकिन अब, समय है कि भारतीयों द्वारा विकसित तकनीक का निर्माण किया जाए। देश और फिर विश्व स्तर पर निर्यात किया जाय। समय आ गया है कि हम अंतरिक्ष उद्योग के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लें, जिसके 2026 तक 558 बिलियन डॉलर तक बढऩे की उम्मीद है।

यह कार्यक्रम मेटावर्स पर आयोजित किया गया, जिससे यह भारत में इस तरह का पहला आधिकारिक कार्यक्रम बन गया।

लॉन्च इवेंट के लिए प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के कस्टम अवतार के साथ-साथ एक अंतरिक्ष-थीम वाले मेटावर्स वातावरण को कस्टम-विकसित किया गया।

पीएम ने बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बनासकांठा जिले के दियोदर में एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। नया डेयरी कॉम्प्लेक्स एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यह प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण, लगभग 80 टन मक्खन, एक लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन संघनित दूध (खोया) और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन करने में सक्षम होगा। आलू प्रसंस्करण संयंत्र विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत आलू उत्पादों जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू टिक्की, पैटी आदि का उत्पादन करेगा, जिनमें से कई उत्पाद अन्य देशों में निर्यात किए जाएंगे। ये संयंत्र स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएंगे और क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। उम्मीद है कि रेडियो स्टेशन लगभग 1700 गांवों के 5 लाख से अधिक किसानों से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री ने पालनपुर में बनास डेयरी संयंत्र में पनीर उत्पादों और म_ा पाउडर के उत्पादन के लिए विस्तारित सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही, प्रधानमंत्री ने गुजरात के दामा में स्थापित जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने खिमना, रतनपुरा-भीलडी, राधनपुर और थावर में स्थापित होने वाले 100 टन क्षमता के चार गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल शामिल थे।

आयोजन से पहले, प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी के साथ अपने जुड़ाव के बारे में ट्वीट किया तथा 2013 और 2016 में अपनी यात्राओं से तस्वीरें साझा कीं। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले कई वर्षों में, बनास डेयरी स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने का केंद्र बन गया है। मुझे डेयरी के अभिनव उत्साह पर विशेष रूप से गर्व है जो उनके विभिन्न उत्पादों में देखा जाता है। शहद पर उनका निरंतर ध्यान रखना भी प्रशंसनीय है। मोदी ने बनासकांठा के लोगों के प्रयासों और भावना की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मैं बनासकांठा के लोगों की कड़ी मेहनत दृढ़ता की भावना की सराहना करना चाहता हूं। जिस तरह से इस जिले ने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है वह काबिले तारीफ है। किसानों ने नई तकनीकों को अपनाया, जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और परिणाम सभी के सामने हैं। प्रधानमंत्री ने आज मां अम्बा जी की पावन भूमि को नमन करके अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने बनास की महिलाओं के आशीर्वाद के बारे में चर्चा की और उनकी अदम्य उत्साह के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है कि भारत में गांव की अर्थव्यवस्था को, माताओं-बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, को-ऑपरेटिव मूवमेंट यानि सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत दे सकता है। काशी से संसद सदस्य के रूप में, प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी और बनासकांठा के लोगों को वाराणसी में भी एक परिसर की स्थापना के लिए आभार व्यक्त किया।

बनास डेयरी में गतिविधियों के विस्तार के बारे में चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी संकुल, पनीर और म_ा प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार में अहम हैं ही, बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आलू, शहद और अन्य संबंधित उत्पाद किसानों की किस्मत बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वोकल फॉर लोकल अभियान पर जोर देने के साथ-साथ खाद्य तेल और मूंगफली के रूप में भी डेयरी का विस्तार कर रहा है। उन्होंने गोवर्धन में डेयरी की परियोजनाओं की प्रशंसा की और पूरे देश में ऐसे संयंत्र स्थापित करके कचरे से कंचन पैदा करने के सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए डेयरी परियोजनाओं की सराहना की।